years, creating a euphoria. This is the result of absence of scientific environment. I request that proper steps be taken to intensify the research effort and increase the production of oils in our country.

(x) Non-payment of sugar cane arrears by three sugar mills of East Champaran district (Bihar) to the cane growers.

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले की तीन चीनी मिलें बाराचकिया, मोतीहारी और सुगाली गन्ना उत्पादक किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर रही हैं। इस से लाखों किसानों को अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इन के घरों में शादी-ब्याह के लिये पैसा नहीं है। कर्ज भी समय पर नहीं मिल रहा है। सरकारी ऋणों का भुगतान ये किसान नहीं कर पा रहे हैं। अपने परिवार के गहनों को इन्हें बेचना पड़ रहा है खेती के आगे के कामों में पैसे के अभाव में प्रगति नहीं हो रही है।

बाराचकिया तथा सुगाली चीनी मिलों का पिछला बकाया भी पूरी भुगतान नहीं हुआ है।

किसान जब अन्दोलन करते हैं तो मिल राज्य सरकार के सिर पर अपना दोष थोप देती है और राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर। इस तरह किसान बैल-तर के मारे बबूल-तर में भटक रहे हैं।

अस्तु मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार किसानों की दुरावस्था को दूर करने में बिहार सरकार पर पर दबाव डाले या कोई दूसरी राह निकाले कि गन्ना किसानों का भुगतान अविलम्ब हो।

(xi) Refusal by Fourth Pay Commission to entertain memorandum submitted by the Sainik School Employees' Association

SHRI AJIT BAG (Serampore): Sir, I am surprised to learn that a Memorandum submitted by Sainik Schools employees Association, Satara, (MP) and Korukunda (Andhra Pradesh) etc. to the fourth Pay Commission has not been entertained on the ground that Sainik Schools are being run by autonomous bodies and hence they cannot come under the purview of the Commission. Every penny that is being spent on these schools comes either from the State Government or the Central revenue. Land, building and maintenance are the commitment of the State and the Centre both. Therefore, the *argument that are run by autonomous* bodies is untenable. In fact, Kendriya Vidyalayas are also run by so-called autonomous bodies. But the teachers and staff of these Vidyalayas enjoy all the facilities as enjoyed by the Central Government employees. Both the KVS and the Sainik Schools teach upto 10 plus 2 standards. Besides Sainik Schools have one more important task before them, i.e., to prepare students for the Defence Services. Even the concessions given on the occasion of Republic Day to the Teachers by the Education Ministry have not been extended to Sainik School teachers. I therefore urge upon the Government to allow Sainik schools to be considered by the Fourth Pay Commission and also take steps to provide Sainik School teachers right to form Association and for representing grievances collectively to the Management.

12.32 hrs.

WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we take up Legislative Bnsiness. The Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 1984 is already under discussion. Yesterday, Shri Rajesh Kumar Singh was on his legs and he had not concluded his speech. The total time allotted for this Bill is 2 hours, out of which 30 minutes have already been taken. We are left with one hour and 30 minutes. I would request the hon. Members to be brief in their speeches.

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कल जो मैं इस चर्चा में भाग ले रहा था, तो मैं यह कह रहा था कि मृत्यु होने पर जो 20 हजार की रकम है, यह बहुत कम है।

"...where the death results from the injury".

ऐसे केसेज में 20 हजार रुपये देने की बात है। यह एमाऊन्ट बहुत कम है क्योंकि हवाई जहाज की दुर्घटना में अगर कोई मर जाता है, तो एक लाख रुपया दिया जाता है और रेल के एक्सीडेंट में अगर कोई मर जाए, तो 50 हजार 70 हजार रुपये तकरीबन मिल जाता है। फैक्टरी में अगर कोई दुर्घटना में मर जाता है, तो उसके लिए 20 हजार रुपये देने की बात है। एक तो यह मुद्दा है, जिसके बारे में मैं कहना चाहता था। नेशनल लेबर कमीशन ने कहा है:

"...that the wage limit for coverage under the Act may be removed altogether."

जहां एक तरफ लिमिट हटाने वाली बात कही है, वहा दूसरी तरफ एक हजार रुपये की बांध दी है। आप देखेंगे कि जो सीमा बांधी गई है सीमा वह इस तरह है:

"Where the monthly wages of a workman exceed one thousand rupees, his monthly wages for the purposes of clause (a) and (b) shall be deemed to be one thousand rupees only."

बोनस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन की है उस के अनुसार 1600 रुपये तक की बात कही गई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यह जो बिल है, यह अधूरा बिल है और इस के स्थान पर एक सम्पूर्ण बिल लाएं। एक बहुत लम्बे समय के बाद आप यह संशोधन ला रहे हैं। 1976 में इस का संशोधन हुआ था और अब 15 वर्ष के बाद आप को मजदूरों की याद आई तो आप ने कुछ संशोधन कर डाले। 4-6 महीने के बाद फिर याद आएगी, तो और संशोधन कर देंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि मंत्री जी इस मामले को गंभीरता से लें। इस में कहीं आप ने देने की बात कही है और कहीं आप ने सीमा फिक्स कर दी है। तो यह नहीं होना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह वाजिब बात नहीं है। आपका जो नेशनल लेबर कमीशन था, उसकी जो रिकमण्डेशंस थीं, जिनको कि इसमें लागू किया गया, वे भी सही मायनों में लागू नहीं हो पा रही हैं। मैं मंत्री जी से, इस संदर्भ में, यह भी जानना चाहूंगा कि कमीशन की जो संस्तुतियां या रिकमण्डेशंस थीं, क्या उन पर सरकार विचार कर रही है? अगर कर रही है तो क्या उन्हें अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया जायेगा?

मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। आपके पालियामेंट में बहुत से हिंदी में विधेयक और अंग्रेजी में बिल पेश होते हैं। मैं हिन्दी के इस विधेयक को और अंग्रेजी के इस बिल को देख रहा था, दोनों में मुझे कुछ अन्तर नजर आया। आपके हिन्दी के विधेयक में लिखा है—

"मृत कर्मकार की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक से गुणा करके प्राप्त रकम के पचास प्रतिशत के समतुल्य रकम, या पच्चीस हजार रूपये की रकम, जो भी अधिक हो।"

इस तरह की छोटी छोटी गल्तियां आपके हिन्दी के विधेयकों में रह जाती हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दी के जो विधेयक हमें आप पढ़ने को भेजते हैं उनमें त्रुटियां न हों जिनसे कि लगे कि हिन्दी की कोई अवहेलना हो रही है। आपके अंग्रेजी के बिल में यह रकम 24 हजार रुपये दी हुई है। अगर आप इसे 25 हजार कर देते तो भी हिन्दी वाली बात जम जाती।

आप इस बिल को बहुत देर से लाये हैं, इससे अपने मजदूरों का अहित किया है और पूंजीपतियों का हित किया है। लेकिन आपको जो देने का क्राइटेरिया है उसमें रद्दो बदल होनी चाहिए। उसमें आप को बोनस एक्ट की बात को भी रखनी चाहिए।

मैं एक और बात रखना चाहूंगा। आपका जो प्रतिकार मिलने का प्रौसीजर है वह बड़ा कम्पलीकेटिड है। किसी की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार के लोगों को पैसा लेने के लिए जाना पड़ता है, वहां लोगों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। अगर कोई पर-

मानेंटली डिसएबल हो गया है तो बीच में एक आदमी पड़ता है और एक लम्बा समय पैसा लेने में निकल जाता है। में आशा करता हूं कि मन्त्री जी इसका ख्याल रखेंगे कि उचित समय पर लोगों को पूरा मुआवजा मिल जाए। अगर वह समय पर उन्हें नहीं मिलता है तो यह भी उनके लिए अहितकर बात है। कभी कभी देखने में यह भी आता है कि मालिक कहता है कि इश्योरेंस कम्पनी पैसा देगी और इश्योरेंस कहती है कि मालिक पैसा देगा। इसी में वर्षो निकल जाते हैं। अगर केस कोर्ट में चला गया तो एक डिसएबल्ड आदमी कोर्ट में कैसे केस को फेस कर पायेगा। यह जो आपकी मुआवजा देने की प्रकृति है इसमें रद्दो बदल होनी चाहिए

मैं एक और कानूनी पहलू की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जहां आपने परमानेंटली डिसएबल होने की बात कही है —

> "A half-monthly payment of the sum equivalent to twenty-five per cent of monthly wages of the workman, to be paid in accordance with the provisions of sub-sections (2)."

आपने 25 परसेंट की बात कही है जो कि आज के जमाने में मुझे कुछ समझ में नही आती है। आज की स्थिति को देखते हुए आपको इसे उचित बनाना चाहिए। मान लीजिए कि कोई काम पर नहीं जाता है। काम पर आदमी तभी नहीं जाता है जबकि वह बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है, बीमारी से या किसी चोट की वजह से। उसमें भी आपने तीन दिन की अवधि की बात दी है। इसमें तीन दिन की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि आये दिन फैक्ट्रियों में और खास तौर से कोयला खानों में खतरनाक घटनाएं घटती रहती हैं और जिनकी वजह से मजदूरों को कम्पेंसेशन देने की बात तक आ जाती है। कभी कभी ऐसे कानूनी पहलू आड़े आ जाते हैं जिनसे कि मजदूरों को प्रतिकार नहीं मिल पाता है। कानून में कोई खामी न रहे, जैसी कि परमानेट डिसएबल्ड वाली बात है, इस पर आप विचार करें। मुझे तो आपकी 25 परसेंट वाली बात समझ में नहीं आती हैं। जब आप मजदूर के हित की बात करते हैं तो आज की स्थिति को भी आपको सोचना चाहिए।

लेबर इंस्पेक्टर के बारे में आम शिकायत है, मैं सब की बात नहीं कहता हूं, लेकिन जनरल्ली लोगों की शिकायत है कि अगर उसको रिश्वत न दी जाए तो वह गलत रिर्पोर्ट देता है, मालिकों के साथ उसकी सांठगांठ बनी रहती है। इसलिए कुछ इसको भी कड़ा करने की जरूरत है।

साथ ही साथ जो नेगलीजेंश होता है, नेगलीजेंस के लिए कभी कह दिया जाता है कि मजदूर ने जानबूझ कर हाथ डाल दिया, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मालिकों की नेगलीजेंश से जो घटनाए होती हैं उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आपका फैक्ट्री एक्ट ढीला-ढ़ाला है, उसको भी मजबूत बनाने की जरूरत है। वह बहुत पहले बना था। आजकल फैक्ट्रयों में मोडरेनाइजेशन हो रहा है, मशीनों का युग चल रहा है, उनमें ज्यादा जोखिम की बात है। इसलिए आपको फैक्ट्री एक्ट में संशोंधन करना चाहिए जिससे कि उद्योगपति जिसके यहां कोई मजदूर काम कर रहा है, उसको कोई क्षति या हानि हो जाती है, वह डिसएबल्ड हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति करमें से उद्योगपति बच न सके। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके लिए सख्त कानून सरकार को लाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे मजदूरों को जोखिम भरे काम करने में भी दिलचस्पी हो। अंत में भी बोनस कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं कि इसके सुझावों पर अमल करना चाहिए और 1000 से बढ़ा कर 1600 रुपए कर देना चाहिए। इसमें डियरनेस अलाउंस वगैरह को भी जोड़ना चाहिए, सब जोड़कर कंपेसेशन मिलना चाहिए तभी मजदूर का आप कुछ भला कर पाएंगे। नहीं तो कोई मजदूरों के हित की ज्यादा बात इसमें नहीं है। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्क्समेन कंपेसेशन बिल 1984 का मैं समर्थन करता हूं। श्रीमन मैं इस सदन में बराबर

देख रहा हूं जब से मैं सदस्य लोक सभा बना हूं और पाटिल साहब मंत्री हैं तब से बराबर मजदूरों के हित के लिए कानून प्रस्तुत हो रहे हैं। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे इम्मीग्रेंट्स के बारे में, लेबरर्स के बारे में, उस कानून को भी संशोधन कर के स्ट्रांग बनाया गया है। इसी प्रकार यह जो वर्क्समैने कंपंसेशन बिल मजदूरी का है, इसके तहत पहले मजदूर की मृत्यु होने पर 10 हजार रुपया दिया जाता था और अंपग होने पर 7200 रुपया दिया जाता था। अब इस 7200 को बढ़कर 20 हजार कर दिया गया है और 10 हजार की जगह 24 हजार कर दिया गया है। यह कानून युवकों के विशेष कर हित में है, इसलिए में इसकी विशेष तौर से प्रशंसा करना चाहता हूं। जितने भी युवक होंगे, जिनकी उम्र कम होगी, उनको अधिक मिलेगा। यह बिल्कुल ठीक चीज होने जा रही है। नेशनल लेबर कमीशन ने जो राय दी है वह वाकई में बिल्कुल सही है। अगर कोई जवानी में अपंग हो जाता है तो पूरा जीवन उसको निकालना पड़ता है। इस संबंध में अधिक अमाउंट देने का प्रावीजन किया गया है। यंग परसन्स को करीब एक लाख रुपए तक दिया जा सकता है और 80 हजार रुपए तक जोखिम भरे कारखाने में काम करते समय दुर्घटना होने पर दिया जा सकता है।

इस तरह से जो कानून में परिवर्तन लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यहां पर जो सुझाव दिया गया है कि 1000 की जगह 1600 रुपया कर दिया जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। 1000 रुपए का जो प्रवाधान है और उसके आधार पर कंपंसेशन दिया जाना है, इनको वर्क्समेन लेबरर की डेफीनेशन में लिया गया है। इससे मैं सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि वर्क्समेन कंपंसेशन एक्ट 1923 में बना और इसमें काफी अमेंडमेंट्स हुए 1976 में अमेंडमेंट हुआ यह समझ में नहीं आया कि हिज-मैजेस्टी डोमिनियन एटसेट्रा प्रोविजन कैसे रह गये ? इस संबंध में आपने जो सुझाव प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल सही है। पिसमील लेजिस्लेशन की बजाय विस्तृत लेजिस्लेशन लाना चाहिए। अगर इसमें देरी होती है तो पिसमील से यह लाभ हो जायेगा कि 7200 प्राप्त कर रहे हैं उनको बीस हजार का लाभ मिल जायेगा। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लेबर और लॉ डिपार्टमेंट की जो एक्जीक्यूटिव मशीनरी है, वह ठीक से काम नहीं करती। यह, बहुत डिले करती है जिसकी वजह से विस्तृत लेजिस्लेशन नहीं लाया जाता। इसलिए, आपकी जो मशीनरी है उसको मजबूत कीजिए। एक्जीक्यूटिव मशीनरी के ठीक ढंग से काम न करने के कारण जो बहुत से लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता। लेजिस्लेशन के बारे में जो कमेटीज फक्शन करती हैं, अगर उसमें डिस्कस करके प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह उचित रहता है। हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए मजदूरों के प्रति विशाल दृष्टिकोण रखना चाहिए और उनके हित में सोचना चाहिए। जितने भी कारखाने हैं, उनमें उनकी पार्टनरशिप और कंट्रीब्यूशन हो ताकि वह महसूस करें कि यह हमारे ही कारखाने हैं, जिससे कि वे पूरी ताकत और योग्यता के साथ राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सकें। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन कुछ संशोधन के साथ। अभी जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि यह कोई काम्प्रीहेन्सिव बिल नहीं है। छोटे पैमाने पर इन्होंने सुधार किया है जबकि इनके पास समय काफी था। 1969 में नेशनल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। पन्द्रह साल का पीरियड कुछ कम नहीं होता है। यदि, चाहते तो इस बिल को पहले भी ला सकते थे और काम्प्रीहेन्सिव बिल भी आ सकता था। औद्योगिक जगत में दुनिया काफी आगे बढ़ रही है और हम अपने वर्कर्स को जो कि इस जगत की रीढ़ है, उनको थोड़ी सी भी सुविधा नहीं दे सकते तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस बिल को लाने

से थोड़ी सी राहत हुई है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके इस सम्बन्ध में कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल लायें। आप उस बात को छोड़िए कि रवीन्द्र वर्मा जी क्या लाये थे और आप लोग अपनी सरकार में क्या कर रहे हैं। मैं इस बिल के सम्बन्ध में अपनी बात कर रहा हूं। जब तक इसकी पूरी व्यवस्था में चेंज नहीं आता, स्थिति सुधर नहीं सकती। यदि हम इस बिल की मूल भावना को देखें तो वह अच्छी है और इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन यह बिल अभी व्यापक नहीं है। जैसा मेरे साथियों ने भी कहा कि इसके ओब्जैक्टस सम्बन्धी स्टेटमैंट में सारे एम्पलाईज को नहीं जोड़ा गया है। मैं नहीं समझता कि भविष्य में आप क्या कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली में ही देख लीजिए कि जितनी यहां फैक्ट्रियां हैं, उनमें काफी संख्या में मजदूर काम करते हैं परन्तु उनके लिए इसमें कोई विधान नहीं है। मेरी कांसटीटूऐंसी में ही दो आदमी थे, जिनमें एक की डैथ हो गई और दूसरे का हाथ कट गया। लेकिन वह एक प्राइवेट फैक्टरी में था, उसे कुछ नहीं मिला। मैंने सब जगह लिखा, लेकिन उसके बावजूद आज तक उसे कोई पैसा नहीं दिया गया है। ऐसे आदमियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए मेरा कहना है कि जिन लोगों के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया है, उनको फायदा होगा, लेकिन उसमें अड़चनें सामने आयेंगी, कहीं प्रशासनिक अड़चनें आयेंगी, कहीं दूसरी बाधायें आयेंगी। अभी हमारे साथी ने लेबर इंसपैक्टर के रोल के बारे में बताया, उसके अलावा भी कई दूसरी बाधायें उपस्थित हो सकती हैं। लेकिन ऐसे लोगों के सम्बन्ध में भी आपको विस्तारपूर्वक विचार करके कोई प्रावधान रखना चाहिए जिनके साथ इस तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। वे लोग सरकारी कर्मकारों से ज्यादा काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन का शोषण होता है और उनके लिए किसी तरह के कम्पैन्सेशन की व्यवस्था विधान में नहीं है। प्राइवेट फैक्टरियों में उनसे बीस-बीस घण्टे काम लिया जाता है परन्तु काम करते समय यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है तो उसके वास्ते उचित मुआवजे की व्यवस्था नहीं है। यदि हम लोगों के नौलेज में बात आ जाती हैं तो भले ही लिखा पढ़ी करके उनको दो-चार या पांच हजार रु० मिल जाए। इसलिए आप सबसे पहले तो सभी तरह के एम्पलाइज को इसमें जोड़िए। दूसरे कम्पैन्सेशन राशि आपने बहुत कम कर रखी है। वैसे तो आपने कहा है कि यह सीमा एक लाख बारह हजार रुपये तक है, लेकिन उसमें तक शब्द का प्रयोग है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपने हवाई जहाज में मरने वालों के लिए एक लाख रुपया क्षति पूर्ति के तौर पर देना स्वीकार किया है, रेलवे दुर्घटना में मरने वालों को भी लगभग इतनी ही राशि दी जाती है, उसी तरह जितने हमारे कर्मकार काम करते समय मर जाते हैं तो उन परिस्थितियों में भी आप उनके लिए एक लाख रुपये की राशि देना निश्चित कर दीजिए ताकि उसको हर हालत में इतनी राशि मिल सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां आने पर हमेशा कोई न कोई टैक्निकल प्वाइंट ढूंढा जाता है कि वह काम पर नहीं मरा, घर जाते समय मरा या ऐसा ही कोई दूसरा प्वाइंट उसके लिए लगाया जाता है। मैं चाहता हूं कि इससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। वह अपने सर्विस पीरियड में मरा, भले ही घर आ रहा था या घर से जा रहा है, लेकिन काम करने के लिए ही तो घर आ रहा था या जा रहा था, फिर आपके जितने कानून बने वे सब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउन्ड्स पर बने हुए हैं, इसी तरह आपको इनके सम्बन्ध में भी मानवीय एप्रोच को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने चाहिएं, न कि टैक्निकल आधार पर। यह नहीं देखना चाहिए, कि वह काम के

पीरियड में मरा या उस समय क्या कर रहा था। हमें ऐसी टैक्निकैलिटीज में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इसके कारण हम लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए इस बिल के सम्बन्ध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, वहीं मेरा आपसे आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके आप मजदूर के हित में एक व्यापक बिल इस सदन में लायें ताकि जो लोग छूटे हुए हैं, उनको भी लाभ मिल सके और जो बेचारे किसी प्राइवेट फैक्टरी में काम करते हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, उनके लिए भी सरकार को कोई व्यवस्था कानून में करनी चाहिए ताकि उनको भी उचित कम्पेन्सेशन मिल सके और उनका शोषण न हो तो मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूंगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की भावना का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, में वर्कमैन कम्पेन्सेशन बिल का समर्थन करता हूं। यह बिल स्वागत योग्य है और इसको पहले आ जाना चाहिये था और जल्दी से इसका फैसला होना चाहिये था। मगर देर आयद दुरुसस्त आयदा जिस प्रकार के प्रोवीजन इस बिल द्वारा किये गये हैं और जिस तरीके के मजदूरों को शामिल किया गया है वह भी स्वागत योग्य कदम है। पहले इसमें 1,000 रु० से उपर वाले लोगों को इनक्लूड नहीं किया जाता था। लेकिन अब हजार से ऊपर वाले लोगों को भी कम्पेन्सेशन की श्रेणी में लाया गया है, यह अच्छा कदम है। मगर इसमें कम्पेन्सेशन हजार रुपये से ऊपर उस मजदूर को मिलते थे तो भी उसको हजार रुपये पर कम्पनसेशन मिलता उतना ही रुपया उसको कम्पेन्सेशन के रूप में मिलेगा, यह ठीक नहीं। क्योंकि ज्यादा पैसा मिलने वाले आदमी को उतना ही मिले जितना कि 1,000 वाले को मिलता था तो उससे लोगों में असंतोष होगा।

दूसरे कि जो कम्पेन्सेशन अमाउन्ट तय किया गया है डैथ के मामले में 7,200 रु० की जगह 20,000 रु० रखा गया है और परमानेंट डिसएबिलमेंट के लिये 10.000 रु० की जगह 24,000 रु० रखा गया है, यह कम लगता है रु० की वैल्यू को देखते हुए। आज की रुपए की वैल्यू को देखते हुए कम्पेन्सेशन देना चाहिये। कम्पेन्सेशन के लिए केवल पे ही नहीं, बल्कि सारे अलाउन्सेज जोड़ कर के कम्पेन्सेट किया जाय तो मजदूर को ज्यादा कम्पेन्सेशन मिल पायेगा। ऐसी व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए।

एक प्रश्न और है काम करते वक्त जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेज मजदूरों को हो जाती हैं, जैसे माइका में काम करने वालों को टी० बी० बहुत होती है और स्थाई रूप से उस बीमारी से क्योर नहीं हो पाते हैं, उसकी लिस्ट आपने इनक्लूड की है, मगर जो लोग बिलकुल डिसएबिल हो जायें इन बीमारियों से उनको कितना कम्पेन्सेशन मिलेगा, किस प्रकार से तय किया जायगा इस सम्बन्ध में शड्यूल 4 में जो दिया हुआ है उसी हिसाब से तय किया जायगा या और कोई व्यवस्था की जायगी, इसको भी आपको साफ करना चाहिये। वरन छोटी-छोटी जगह पर कम्पेन्सेशन कमिश्नर के आफिस में जब मुकदमे चलते हैं तो बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा अच्छे वकील खड़े कर दिये जाते हैं जो तरह-तरह की कानूनी खामियां बताकर दिक्कतें पैदा करते हैं और बेचारा मजदूर परेशान होता है। हमारे यहां भीलवाड़ा में मेवाड़ टैक्सटाइल्स में एक मजदूर की काम करते वक्त 4 उंगलियां कट गई उसको वर्कमैन कम्पेन्सेशन कमिश्नर ने 20 000 रु० का अवार्ड दे दिया। लेकिन चूंकि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का मालिक बड़ा पैसे वाला आदमी है उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सभी जगह हार जाने के बाद भी आज तक उसने एक पैसा नहीं दिया। तो इस तरह का भी कोई प्रावधान करना चाहिए कि अगर कम्पेन्सेशन कमिश्नर उसके सम्बन्ध में कोई फैसला कर दे तो वह पैसा मालिक को सरकार के खजाने में जमा कराना होगा उसके बाद ही वह अपील में जा सकता है। अगर ऐसा

प्रावधान नहीं होता है तो मालिक गरीब मजदूर को थका देगा।

वह कहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य स्थानों में लड़ेगा? इसलिए इस प्रकार का प्रावधान कानून में होना चाहिये कि जब कम्पेंसेशन का एमाउन्ट कम्पेंसेशन कमिश्नर तय कर दे तो वह फौरन कचहरी में जमा करा दे। इसकी निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मजदूर को बाद में कोई झंझट न हो।

वर्कमेंन कम्पेंसेशन कमिश्नर के बहुत से अधिकार आपने लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियो को दे रखे हैं, जैसे हमारा भीलवाड़े में लेबर वैलफेयर आफ़िसर रहता है, उसको आपने यह अधिकार दे रखे हैं। एसिस्टेंट लेबर कमिश्नर अजमेर में रहता है उसको आपने ये अधिकार दे रखे हैं, मगर बहुत सी जगह आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं। भीलवाड़े में वैलफेयर आफिसर के पद पर एक साल से किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। लोग कम्पेंसेशन केसेज लेकर कहां जायें, कौन उनको डिसाइड करेगा? एसिस्टेंट लेबर कमिश्नर वहां पर बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए जहां आपने वर्कमेंन कम्पेंसेशन कमिश्नर के कुछ अधिकार लेबर आफिसर्स को दे रखे हैं वह अधिकारी ही अगर वहां पर न हों तो उस हालत में आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ अधिकारी नियुक्ति हों और जल्दी से जल्दी इन मुकदमात के फैसले हों।

भीलवाड़े में एक साल से लेबर आफिसर की नियुक्ति नहीं हुई है और वहां इतने मजदूर हैं कि अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। वहां पर माइका की माइन्स हैं, सोप-स्टोन, एसबैस्टोज, स्टोन, सैंड स्टोन, खाड़िया मिट्टी की खानें, जिंक, राक फास्फेट की बहुत खाने हैं जिनमें एक लाख से ज्यादा मजदूर उस जिले में काम करते हैं। एसिस्टेंट लेबर कमिश्नर के दफ्तर होने से मजदूरों को फायदा मिल सकता है, वह वहां पर नियुक्त होना चाहिए, लेकिन एक साल से लेबर आफिसर ही गायब है। आप बतायें किस तरह से वहां के मजदूरों को सहूलियत मिल सकती है?

आज आपने इस कानून में बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाईज को भी इन्क्लूड कर लिया है। आपने इसमें मिकदार को बढ़ा दिया है कि 1 हजार से ऊपर पाने वालों को भी कमपेंन्सेशन दिया जा सकेगा। आज लाखों सैंट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाई हैं जिनको 1 हजार से ज्यादा मिलता है, उसी प्रकार के मजदूर भी इसमें शामिल हो गये हैं। आज इस तरह से बहुत बड़े तबके को इस कानून से फायदा मिलेगा।

इस कानून को लाने का आपने अच्छे ढंग से प्रयास किया है। इसमें आज कम्पेन्सेशन बढ़ाने की आवश्यकता है।

कुछ लोगों का टैम्परेरी डिसएबलमैंट हो जाता है, जिन कारखानों में मजदूर काम करते हैं, वहां ई० एस० आई० लागू है, उसके जरिये अगर किसी की छोटी उंगली कट गई या छोटा डिसएबलमैंट हो जाये तो उसका फैसला वहां के लोकल ई० एस० आई० के अधिकारी कर देते हैं और उनको पेमैंट कर सकते हैं, मगर आपको देखना चाहिए कि जो ई० एस० आई० स्कीम आपने चालू कर रखी है, उसमें वहां पैसे की व्यवस्था नहीं है। वहां लोगों को न दवाई मिलती है और न कम्पेंसेशन का पैसा मिलता है। मजदूर इसके लिये मारे-मारे फिरते हैं। इसके सम्बन्ध में आप तवज्जह दीजिये कि अगर छोटे-छोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उसके बारे में तुरन्त मजदूर को पैसा मिले और इस प्रकार की स्कीम को आपको मजबूत करना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Have you given any amendment to incorporate this suggestion ?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): He can suggest it even now.

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस कानून से लोगों को काफी राहत मिलेगी। आपको यह भी देखना चाहिए कि जिनकी डैथ हो जाती है या

परमानेन्ट डिसएबल हो जाते हैं, इस प्रकार के लोगों को टाइमली रिलीफ इससे मिलता है या नहीं ?

क्या मंत्री महोदय एक काम्प्रिहेंसिव बिल में यह प्रावधान करेंगे कि जो एमाउंट डिसएबलमेंट या डेथ के सम्बन्ध में बनता है, पहले वह एमाउंट उस दफ्तर में जमा हो जाए और उसके बाद आपोजिट पार्टी को लड़ने का अधिकार हो।

संगठित लेबर के सम्बन्ध में ट्रेड यूनियन्ज काम करती है, लेकिन असंगठित लेबर, कट्रेक्ट लेबर और इम्मीग्रेन्ट लेबर के बारे में भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। लेबर इन्स्पेक्टर की यह ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर किसी के हाथ-पांव कट जाते हैं या डेथ हो जाती है, तो उसका केस दर्ज कराए और पेमेंट दिलाए।

इन शब्दों के सांथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। जो कठिनाइयां मैंने रखी हैं, मंत्री महोदय उनको दूर करने का प्रयत्न करें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Ramavatar Shastri may speak.

At least all those hon. Members who have spoken should remain till the Minister replies.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Why should they ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is a formal suggestion.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You must know how far the Government accepts your suggestion; for that you must wait.. You take it or reject it. I would say that any hon. Member who speaks must remain and be present when the Minister replies.

(Interruptions)

रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रमजीवी मुआवजा (संशोधन) विधेयक, 1984 का मैं एक संशोधन के साथ समर्थन करता हूं। यह कानून 1923 में बनाया गया। इसका पहला संशोधन 1976 में हुआ और दूसरा संशोधन हम लोग अब कर रहे हैं। मेरी भी राय है कि अगर मजदूरों के जीवन से सम्बन्धित तमाम मसलों को लेकर एक विस्तृत विधेयक बनाया जाता, तो ज्यादा अच्छा होता। टुकड़ों टुकड़ों में विधेयक बनाना ठीक नहीं होता है। इसी दृष्टिकोण से एक विस्तृत विधेयक लाने की आवश्यकता है, जिसमें तमाम बातों को समाहित किया जा सके।

इस विधेयक में आकुपेशन डिसीजिज या उपजीविका-जन्य रोगों की चर्चा की गई है, जिनमें 34 रोगों का उल्लेख है। उनमें कारखानों में काम करने की वजह से होने वाली करीब करीब सभी तरह की बीमारियां आ जाती हैं। मजदूर की बीमारी ठीक तरह से पकड़ा जा सके, इसका पता लगाने के लिये सरकार की मशीनरी बड़ी चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए। ताकी सचमुच में जो बीमार है उसका पता चल जाए और अगर अंग-भंग हो गया या मृत्यु हो गई तो हम जान लें कि इस वजह से मृत्यु हुई। तो इसके लिए कोई न कोई विधि आपको निकालनी होगी।

तीसरी बात यह है कि आपने मजदूरी की सीमा हटा दी है। पहले आपने एक सीमा बांध रखी थी कि उससे ज्यादा मजदूरी पाने वाले को मुआवजा नहीं देंगे। लेकिन अब आपने सीमा हटा दी जो कि स्वागत-योग्य है।

इसी के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा। क्लाज (4) में जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें कहा गया है :

> "Where the monthly wages of a workman exceed one thousand rupees, his monthly wages for the purposes of clause (a) and (b) shall be deemed to be one thousand rupees only."

इसका अर्थ यह हुआ कि दो हजार जिसकी तनख्वाह है उसके लिए भी आप एक हजार ही मानेंगे तो मैं समझता हूं यह मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं इस एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप डिलीट कर दीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can suggest Rs. 1600 instead of Rs. 1000/-

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : My first amendment is explanation to clause 4 should be deleted.

The ceiling has been abolished. It is very good. The compensation will even then be restricted to a monthly wage ceiling of Rs. 1,000/-. If this amendment is not acceptable to the Government, then at least a monthly wage ceiling should be Rs. 1600/- instead of Rs. 1000/-. Rs. 1600 has been the standard monthly wage ceiling fixed by the Government in different legislations.

विभिन्न कानूनों में आपने 1600 तक रखा है तो इस कानून में आप 1000 क्यों करना चाहते हैं ? आप अपने रास्ते से पीछे क्यों जा रहे हैं ? आगे आने का समय है, पीछे जाने का नहीं । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस अमेन्डमेंट को स्वीकार कर लेंगे तो श्रमजीवियों को नुकसान नहीं होगा और आपकी मंशा भी यही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे । मरने पर उनके परिवार जनों को और जिन्दा रहने पर, यदि अंग-भंग हो जाते हैं, तो उस स्थिति में सरकार सहानुभूतिपूर्वक उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करे इस दृष्टिकोण से इस एक्सप्लेनेशन को हटा देना आवश्यक है ।

मुआवजे की रकम के बारे में मुझे यह कहना है कि जान सबकी बराबर है । कोई हवाई जहाज में मरे, ट्रेन में मरे या कारखाने में काम करते हुए किसी अकूपेशनल डिजीज का शिकार होकर मरे-जान सभी की बराबर है । और आप तो समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद में जान एक ही होती है इसलिए मुआवजे की रकम भी सभी के लिए एक लाख होनी चाहिए ।

आप कहते हैं कि छोटे कारखानेदार कहां से देंगे तो इसमें बड़े-बड़े कारखानेदार हैं, बिड़ला जी भी हैं, उनकी रौरो माइन्स हैं जहां एस्वेस्टास शीट्स का काम होता है । इसी तरह से इसमें ज्यादातर इजारेदार ही होंगे, कारखानों को चलाने वाले फिर उनके साथ रियायत क्यों ? जब रेलवे में एक लाख, हवाई जहाज में एक लाख है तो इन कारखानेदारों को भी एक लाख देना चाहिये यह मेरा सुझाव है ।

आखारी बात मैं कम्पेंसेशन यानि मुआवजे के बारे में कहना चाहता हूं । इसकी अदायगी में बहुत विलम्ब होता है, मेरी दृष्टि में विलम्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरने वाला तो मर जाता है, उसके बाद में उसके परिवार के लोगों को परेशान होना पड़ता है । घूमते-फिरते चक्कर लगाते, कम्पेंसेशन कमीशनर का दफ्तर खोलने में, बड़े बाबुओं को पकड़ने पर उसको पता नहीं कितनी घूस देनी पड़ती है । मैं चाहता हूं कि आप एक सीमा बान्ध दीजिए कि इतने दिनों के बाद कम्पेंसेशन मिल जाएगा । मरने के बाद या उंगली कट जाए या अंग कट जाए या शरीर अंग-भंग हो जाए—हर स्थिति में एक सीमा निर्धारित करना जरूरी है । यदि आप सीमा निर्धारित नहीं करेंगे तो वह बेचारा गरीब चक्कर लगाते-लगाते मर जाएगा और उसको जितनी कम्पेंसेशन की राशि मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलेगी । मिलने के पहले ही उसको कितनी राशि अपनी जेब से खर्च करनी पड़ेगी इसके लिये आपको कोशिश करनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि क्लाज-4 के एक्सप्लेनेशन को हटा दें, नहीं तो कम से कम एक हजार रु० के बदले 1600 रु० कर देने चाहिए ।

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is not a bad Bill. But I deliberately avoid to say that it is a good Bill because I wanted a comprehensive Bill on the subject.

So far as this compensation is concerned, in my opinion, this compensation should be based on the age-group and in any case, it should not be less than Rs. one lakh. Upto 30 years, if anybody becomes disabled, he should be paid Rs. 1.5 lakhs. Between 30 and 50 years, it should be Rs. 1.25 lakhs and above 50 years, it should be Rs. 1 lakh

as compensation. This is my suggestion and I would like to request the hon. Minister to look into it and try to help the workers accordingly.

In a railway accident, if anybody dies, as many Members have pointed out, his next heir would get Rs. one lakh as compensation. But if a worker of Railways dies in the same accident, he does not get the same amount. Therefore, this kind of difference must be eliminated and some provision should be provided that to give that much of compensation to the workers also. Similarly, in other accidents also, like aeroplane accident, there should be no difference and the workers must be paid the same amount which is being paid to the passengers.

Now, Sir, there should be a provision in the Bill that if a worker dies while working, a member of his family must be given employment. Suppose his children are minor, then in that case, one of them must be given a job when he becomes major. There must be a provision of this kind. I know a case which I have referred to the five successive Finance Ministers of those country since 1977 till this date and the person did not get the job so far. One person was working in the Imperial Bank. He died during his service period.

MR. DEPUTY SPEAKER : You have represented the case to the five successive Finance Ministers. It is high-time that you become the Finance Minister and implement the scheme.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I do not know what will happen-whether this will be done during the tenure of this Government or not. I wrote to Shri H.M. Patel, Chaudhury Charan Singh, Shri H.N. Bahuguna, Shri R. Venkataraman and the fifth Finance Minister Shri Pranab Mukherjee. I referred this case to all of them. His father was working in the Imperial Bank. He died during the service period. At that time, his son was minor. He did not get the job. The authorities of the Imperial Bank assured that he would definitely get the job when he become major. In the mean time, the Imperial Bank was merged with the State Bank of India. Now, the State Bank of India authorities are continuously reluctant to provide job to this person. While taking about this issue, he gave them the case and quoted some examples also. But they are not at all prepared to listen. Mr. Pranab Mukherjee had assured me that he will definitely do something for the boy. But he also could not do anything so far. For the last two years, he has been trying. He speaks to the officers; the officers come and give some explanation. I do not know whether the Finance Minister gets satisfied or not. I was having some hope-with every Finance Minister. But nobody could solve the problem. I do not want to differentiate anybody in this matter.

MR. DEPUTY SPEAKER : You continue to pursue the matter.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I have been pursuing it for the last 7 years.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : On compassionate grounds, they can give some job.

SHRI HARIKESH BAHADUR : In many organisations, like the Railways, there is a provision like that. They give jobs on compassionate grounds. There should be a compulsory provision like that in every Department of the Government.

MR. DEPUTY SPEAKER : For your information, as a former P&T employee myself, I know, if any employee dies while in service and, if none of his sons is employed anywhere, one of his sons is given a job. It is there in the P&T Department.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Now-a-days, it is not being practised.

MR. DEPUTY SPEAKER : If any employee becomes an invalid, either his sight is lost or he loses a limb, there also, if none of his family members is employed anywhere, one member of his family is given a job. I myself helped them to get the jobs. I got it done myself when I was a trade unionist. You can also insist on that. It is a nice suggestion that you are making.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I am always making nice suggestions. It is for the Government to accept them.

There should be a provision like that. Whenever any employee dies while in service, in any Department, one member of his family, son or daughter or wife, should be given a job even after 15 to 20 years. In some of the railways, it is there. In the N.E. Railways, it is 20 years. We helped many people to be provided with jobs on compassionate grounds.

About the casual labour also who are working in various Departments, this facility must be given to them, specially in the railways.

So far as the contract labour and the labour going outside the country is concerned, for them also, this provision should be there. That is why we have demanded a comprehensive Bill.

Further, if any worker dies due to negligence of the employer, because the employer does not provide adequate safety measures, etc., in that case the employer must be punished. There should be a provision for that also.

Lastly, I support the amendment proposed by Shri Ram Avtar Shastri and I hope, the hon. Minister will accept it. I hope, he will look into all the suggestions which have been made here.

With these words, I support the Bill.

*SHRI S.T.K JAKKAYAN (Periakulam) : Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir I rise to say a few words on the Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 1984.

The parent Act was amended in 1976 and after 8 years this amendment has been brought forward by the Labour Minister. The Labour Commission submitted its Report in 1969. It is regrettable that many purposeful recommendations of the Labour Commission, have not yet been implemented. This Bill, which seeks to give effect to one of the recommendations of the labour Commission, is an illustration of lethargic functioning of the Government which swears by the name of welfare. Why should the Government take such a long time to give legislative backing to the recommendations of Labour Commission ? We had signed the I.L.O. Convention long time ago. The I.L.O. Convention has stipulated certain rates of compensation for death disability due to accidents. These rates are being incorporated in this amending Bill now. Anyway, the Government have taken belated steps for implementing the recommendation of the Labour Commission and also of the suggestions contained in the I.L.O. Convention for the good of the labour. On behalf of the workers of the country, I extend my whole-hearted support to this Bill and I am sure that this Bill will receive the unanimous approval of the House. I convey my gratitude to the Labour Minister for havnig taken this opportunity to make some other necessary amendments also to the parent Act, which was passed by the British Government in 1923. All these years the Act contained the words "His Majesty's dominions or in any other foreign country". We should not have taken 36 years for removing this obnoxious and shameful reference to "His Majesty's dominions" in this Act which is under impelmentation in the Independent India. I wonder why should we continue to date the laws of our country to the British period. I want to know what is the problem in dating this law as Workmen's Compensation Act, 1948. All the Acts passed during the period of British Administration must be dated after 1947 when we became Independent. They must also be modified to be in consonant with the modern times. I request the hon. Labour Minister to pay attention to this problem also and do the needful.

The employment opportunities are getting reduced in the organised sector. The Central Government as also the State Governments have been doing everything for the welfare of workers in the organised sector. Recently our hon. Prime Minister stated that the workers are the backbone of the nation. We must do everything to strenthen the backbone of the nation. But it must also be remembered that our nation is agricultural-based. The economic growth depends upon agricultural growth. We have 25 crores of agricultural workers who contribute their blood and sweat for agricultural growth. Their lot has remained unchanged all these years. The Labour Minister will say that the Minimum Wages Act will take care of them. But that is not enough. In this Bill the ceiling limit of Rs. 1000 for the entitlement of compensation has been removed. While I welcome this, I have to say that the monthly income of an agricultural I worker is not even Rs.100. The workers in the organised sector do not go beyond 10% of agricultural workers in the country. When we do everything for 10% workers, we neglect the interests of 90% workers of the country. When the agricultural worker dies due to natural calamity or due to accident or becomes disabled while working, there is no compensation for him. I appeal to the hon. Labour Minister that

*Original speech was delivered in Tamil.

he should bestow his attention to improving the lot of agricultural workers also.

I would also refer to another important issue. So long as the contract labour system and the casual labour system are allowed to perpetuate in our country, the labour welfare laws have no meaning and purpose at all. The compensation benefit will not accrue to 2 lakhs of casual labour on our Railways. The compensation law will not be applicable to the contract labour system being followed by Central Public Sector undertakings. If the Government want to ensure the welfare of workers of the country, then the contract labour system and the casual labour system must be eliminated forthwith. When the Government engages contract labour and casual labour, the private sector industrialists take full advantage of these two systems. Hence I demand the abolition of contract labour system and casual labour system.

The fatal accidents are increasing in the factories. The industrailists do not implement the safety law effectively. They do not provide even fire fighting equipment, though it is a legal requirement. They also do not care for immediate disbursal of compensaion to the dependents workers who are dead in the accidents and disabled in such accidents. The Labour Inspectors must be directed to take punitive steps against such ercalcitrant employees. The Labour Inspectors should also be directed to help the dependents of workers regarding the facilities available under the labour welfare laws. They have to be helped in filling up the plethora of forms. All the labour laws are in English and Hindi and the Minister of Law has stated that efforts are being made to have them in regional languages. Unless all these labour laws are in regional languages, they do not benefit the illiterate families of workers. They are cheated by intermediaries. They cannot question the inordinate delay in getting the benefits.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Government of Tamil Nadu have translated all the Labour laws in Tamil.

SHRI S.T.K. JAKKAYAN : I am referring to all the regional languages.

The labour Minister should provide exclusive funds to the States for translating all the labour laws in the regional languages.

I do not want that this law should also become subjected to the whims and caprices of industrialists. I am given to understand that more then Rs. 200 crores are due from the industrialists under the Employees' Provident Fund Act and the Employees' State Insurance Act. They are utilising the workers' money for their personal use. I want effective enforcement of the Workmen's Compensate Act because this is applicable to the helpless dependents of workers who are dead and the works who become disabled. The Central Government should take to task the erring employers.

Annually, we are getting a copy of the Pocket Book of Labour Statistics prepared by the Ministry. We are not able to understand the contents of this book. I want the hon. Minister to look into this and improve this publication so as to make it understandable.

Many hon. Members refrred to the fact that this is a half-backed measure. The Minister also in his preliminary remarks pointed out that a comprehensive law is under preparation. I request him to expendite the preparation of this comprehensive law so as to ensure the welfare of our workers and their families. With these words I support this Bill and resume my seat.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : The Bill contains three basic proposal and these are welcome proposals. One proposition is the removal of the leagal constraints to the eligibility for compnsation for those whose earnings exceed Rs. 1000. This is a welcome proposition. The second proposition of the Bill is linking of the compensation with the age. This is all he more a welcome proposition. The third proposition is to update the occupational diseases in tune with the ILO Schedule. These are the three basic propositions of the Bill under consideration. So far as these propositions are concerned, I have got no difference of opinion. But what prompted me to take part in the debate is that to me it appears that a higher or a larger amount of compensation is, according to me—I do not accuse him-presumed to be the substitute for safety regulations. No worker in our country is willing to have a higher compensation than to be in a working condition which ensures a greater amount or a greater measure of security. My charge is that in our country the safety measures

are being deliberately neglected and the Government's role has been passive. For example, I want to give you some indication of the statistic to imagine the magnitude of the problem. The problem means disablement permanent or temporary, due to on-implet-mentation of the safety rules or sefety regulations. According to the statistics collected by the *Economic Times*. 2.5 lakhs workers are maimed, crippled or otherwise disabled every year. About 2.5 lakhs workers every year are crippled, maimed or disabled. Approximately about 1500 or something of that nature eventually lose their life. I am not speaking about the unorganised sector. This is the magnitude of the problem. That is, about 2.5 lakhs of our workers engaged in industrial undertakings are exposed to this kind of disablement every year. This is at the level of the present day mechanisation of our industry. Now I am glad the Prime Minister of the country made a statement saying that we should go in for further mechanisation. It is necessary if we want to cope with the situation. Then I apprehend that with faster mechnisation this figure or this number of workmen to be exposed to safety hazards will be increasing. What is at the present moment ?

Sir, there was a study made in the chemical industry and, from that random study, only one sector, that is, in the chemical industry, 47% of the factories lacked the proper First-Aid. They have no properly equipped First-Aid arrangement in the factories ; 30% of them have no proper medical rules at all ; 73% of them have not instituted any periodical health check for their employees.

Therefore, Sir, my comment and my conclusion is that the existing safety regualtions are observed more in breach than on the adherence. If we come to the question of other industries, I wanted to draw the attention of the Minister to the Coalmines—my friend, Mr. A.K. Roy can tell about it in a much better way than me—there is no safety measure in the coalmines. I would remind you of the trauma in the Chas Nala colliery accident in which 400 people were killed. They were killed because of no fault of theirs but because the management did not adhere to the safety measures as provided for under the laws. This is the magnitude of the situation. If you want that the compensation should be increased, would these 400 Chas Nala victim's families be more happy to have a greater amount of compensation ? They will be happy and the whole—countrymen will be happy and even House will be happy if, in the coalmines, the safety regulations are implemented more efficiently. Therefore, Sir, according to me, it is not the question of providing compensation but efforts should also be made more in the direction of implementing the existing safety measures and to improve them. This is my general comment. So far as other points are concerned, they have been dealt with by many friends. As regards the explanation, it seems to me that this is the parameter in the thinking of the Government. But, when you have decided that all those who earn more than Rs. 1,000 should be brought within the purview of the Act, what is the rationale behind this ? I will be glad if you can explain the rationale of not entitling others to have the compensation. Is it on the basis of the actual cake available to them ? What is your rationale ? I have not been able to understand the logic of it—the rationale of it. Therefore, Sir, I shall be glad if he will take this opportunity to explain to us the rationale of depriving the workmen who are earning more than Rs. 1,000 and not making them the beneficiary of this beneficial compensation commensurate with their pay.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I also want to know how this rationale has been fixed.

SHRI CHITTA BASU : From my side I would say that the only rationale thing is to help the employer.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I want to know from the Minister—not from you.

SHRI CHITTA BASU : Anyway, from may side if you want to know I can say that they have covered a larger number of workmen keeping in mind the interests of the employers. They want at least to help them by way of reducing the compensation payable. Therefore, I do not accuse him. This is what is called a mixed socialism like water mixed with milk. This is not the occasion to discuss socialism and their philosophy.

Sir, I conclude by saying that there is need for the improvement of the safety measures. There should be a law and there

should be a monitoring agency to see that the safety measures are being properly implemented and it has also to be seen that a comprehensive Bill incorporating the suggestions made by the various Members is brought forward for the consideration of the House at the earliest.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am very happy that almost all the hon. Members who participated in the debate have welcomed this piece of legislation without any reservation. This is a small bill and also a non-controversial bill and this Bill is in the interests of the workers. Many hon. Members wanted to know the reasons for the delay in bringing forward this Bill. I need not go into the details but I can only tell the House that before we come to the House with a Bill for introduction and consideration several formalities have to be gone through and at several levels the proposals are scrutinised and ultimately it is for the legislative wing to prepare the bill. The hon. Members are aware-and I do not wish to blame anybody-that legislative wing is overburdened with work and the hands that are available for drafting the bill are not adequate and every Ministry wants that their proposals should be drafted in the form of a Bill by giving priority. Therefore, there is some delay and I am sorry for that.

If I waited for a comprehensive Bill it would have been further delayed. Therefore, I thought because of the delay workers should not suffer and in the interest of workers I thought at least the amendments which are of urgent nature should be brought before House and got approved.

Almost all the hon. Members demanded a comprehensive Bill to be brought before the House as early as possible. In my introductory remarks I made it clear that I am bringing a comprehensive Bill and it consists of as many as 50 to 60 amendments. The comprehensive Bill is being drafted now and I will try my best to introduce the Bill in the next monsoon session of Parliament.

Sir, so far as this Bill is concerned the employees who are working in the hazardous employment will get the benefit of this but some hon. Members wanted to know about the employees who are working in other establishments which are not hazardous. I can only say that those who are working in other establishments which are not considered to be hazardous, if they are covered by ESI then they get compensation under ESI and the rate of compensation under ESI is much more than that we are going to prescribe now.

Several hon. Members felt that the quantum of compensation that is suggested in the Bill is low. I have already made it clear in my introductory remarks that so far as the quantum of compensation is concerned the rates of compensation are based on the rates specified in the ILO convention concerning the minimum standards of social security.

This is on the basis of the rates specified in ILO convention and the only departure or deviation which we have made is, while calculating compensation, the wage ceiling of Rs. 1,000 is put. My friend Mr. Ramavatar Shastri feels that this ceiling or this explanation defining the wage ceiling should be removed. I made it clear why we have put the ceiling. ILO convention also says that certain restrictions may be put while fixing compensation. Some of the hon. Members have spent almost all their life in trade unions and they know things much better. I wish to point out that this is a compensation the employer is expected to pay. It is not Government which is paying the compensation. In don't subscribe to the view that every employer in the country is a multimillionaire and every worker is a pauper or poor person or oppressed and depressed and is suffering. I don't subscribe to this view. What about those having small scale industry employing 10 or 12 people ? We don't know how that industry is running, whether it makes profit or not. It depends upon the capacity of the employer to pay. Suddenly we have made a big jump. In the case of permanent total disablement from Rs. 10,800 the amount has been increased to Rs. 24,000. Similarly the minimum rates of compensation for death would be Rs. 20,000 as against Rs 7200. The maximum existing is Rs 30,000 which is increased to Rs 90,000. For permanent total disablement from Rs. 42,000 we are going up to Rs 1,12,000. This is a big jump. Let us see how it is going to work. We have to look into the condition of the employer also and his capa-

city to pay. We cannot make a big jump which may become intolerable for the management and the employer.

About migrant works, I wish to make this clear. So far as this Act is concerned whether it is migrant worker or casual or contract worker, everybody working in hazardous employment is entitled for this compensation. I agree with some members that the migrant workers find it difficult to get the compensation because they work here and they go back to the places and the compensation commissioner finds it difficult to work out the compensation. I would say that the safeguarding of the interest of the migrant workers in the matter of settlement of claims under Workmen's Compensation Act, 1923 has already been engaging the attention of the Government. The matter was discussed at the meeting of the Labour Secretaries held in September, 1983. State Governments were advised to frame the necessary rules under Section 32 of the Act for transfer of the claims in respect of migrant workers to the Commissioner of the area where the dependents of the workers reside particularly where the employer has expressed a desire not to be made a party to the proceedings. We are thinking how best to do it so that migrant worker will get compensation as early as possible.

Another complaint made was that claims were not settled in time. It is true that in certain cases a long time might have been taken. It is because Compensation Commissioners are not adequate in number.

Recently we have taken up this matter with all the State Governments. We have issued. Circular letters to all the State Governments and we have requested the State Governments to see that Compensation Commissioners are appointed in adequate number. In addition to that, so far as this Act is concerned, in the existing Act, Section 4 (a) provides for payment of compensation within a month, that is, from the date it falls due. In case of failures to pay compensation by due date, the employer is liable to pay interest at the rate of 6%.

Now, we are thinking of increasing this rate of interest from 6% to 12%. But we are going to make this provision in the comprehensive Bill. Another provision we are thinking of in the comprehensive Bill is to make a specific provision that in every case of fatal accident, the employer shall deposit the amount of compensation with the Commissioner within 30 days of the date of accident and he my raise the issue, if any, regarding the liability for payment of compensation only after depositing the amount of compensation. We are making it compulsory that he should first deposit the amount and then only he can raise dispute over the claim.

Then, Sir, in the comprehensive Bill we are thinking of another important proposal, that is, the Government has accordingly decided to introduce a scheme of compulsory insurance under the Workmen's Compensation Act. This will be included in the Comprehensive Bill. Some hon. Members wanted to know why 25% for temporary disablement. I would make it clear that it is not 25% so far as temporary disablement is concerned. In the case of temporary disablement, the worker gets every fortnight the compensation, That is why we say 'every fortnight'. That means, per month, he gets 50%, as in the case of permanent disablement. Since he is being paid every fortnight 25%, is amounts to 50% when we work it out monthly, that is, 50%.

Some hon. Members wanted to know while calculating this compensation, whether only pay is taken into consideration or DA and other benefits are also taken into consideration. I want to make it clear that the term wages has been defined to includes any privilege or benefitt which is capable of being estimated in money other than DA or contribution paid by the employer towards pension, provident fund, etc. The term wages would therefore include DA and all other allowances except the travelling allowances. So, DA and other allowances are taken into consideration for the purpose of calculating the pension.

Hon. Member, Shri Harikesh Bahadur has suggested an importanl point that there should be a provision for providing employment for at least one dependent of the deceased employee. The Government policy is very clear in this matter. There are administrative instructions on the Government side for providing employment to dependent of the deceased employee who dies in harness. The practice in the Government side has been recently commended to the Central Organisation of employers, with the request to advise their members to consider adopting

a similar practice. These are the few points which the hon. Members have made out and I have clarified the position. Again, before I conclude I would like to say that I am grateful to all the hon. Members who have given their unqualified support to this piece of legislation.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration".

The motion was adopted

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up Clause by Clause consideration of the Bill. The question is :

"That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bills

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL) : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.55 hrs.

UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) AMENDMENTS BILL. ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE (GOODS OF SPECIAL IMPORTANCE) AMENDMENT BILL

UNION DUTIES OF EXCISE (ELECTRICITY) DISTRIBUTION (AMENDMENT) BILL AND ESTATE DUTY (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHANA) : On behalf of SHRI PRANAB MUKHERJEE, I beg to move :

"That the Bill to amend the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1979, be taken into consideration."*

"That the Bill further to amend the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, be taken into consideration".*

"That the Bill to amend the Union Duties of Excise (Electricity) Distribution Act, 1980, be taken into consideration."*

"That the Bill further to amend the Estate Duty (Distribution) Act, 1262, be taken into consideration."

The hon. Members are aware that the Finance Commission is required to make recommendations to the President under Article 280 of the Constitution in regard to the taxes and duties which are to be shared with the States, and the interee distribution among the States of the share of States. The four Bills which I move today arise out of the recommendations of the Eighth Finance Commission made in its interim report for the year 1984-85. This report along with the memorandum on action taken was laid on the Table of the House on 9.12.1983, as required under Article 281 of the Constitution. In its interim report, the Eighth Finance Commission has *inter alia* recommended that the existing arrangement in regard to distribution of Union Excise Duties and Estate Duty on property other than agricultural lands may be continued in 1984-85 subject to such modification as may be made in the final report.

13.58 hrs.

(SHRI R.S. SPARROW *in the chair*)

The final report of the Commission was submitted to the President on the 30th April, 1984 and it will take some time to process the recommendations made in that report and lay it on the Table of the House along with memorandum of action taken thereon. This will be possible only in the next session of Parliament.

In the meantime, the first instalment for the current year of the share of Statis in Union excise duties is to be paid in May.

---

* Moved with the recommendation of the President.